



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, २८ सितम्बर, १९९५, ६ अक्टूबर, १९९५

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४; २८ सितम्बर, १९९५

संख्या १-४४/९५-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हि० प्र० विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) मंजोर्जन विधेयक, १९९५ (१९९५ का

विधेयक संख्यांक 11) जो दिनांक 28 सितम्बर, 1995 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 1995

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित है:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त
नाम।

1971
का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसको पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में, "एक सौ पच्चास" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "दो सौ" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4
का संशो-
धन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में—

धारा 6-ख
का संशो-
धन।

(क) उप-धारा (1-अ) में—

(1) खण्ड (i) और (ii) को खण्ड (ii) और (iii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और पुनः संख्यांकित खण्ड (ii) से पूर्व निम्न-लिखित खण्ड (i) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(i) यदि उसने एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सेवा की है तो तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रतिमास";

(ii) पुनः संख्यांकित खण्ड (ii) में, "तीन सौ पचहत्तर" शब्दों के स्थान पर "सत्तर सौ पच्चास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) के खण्ड (ii) में, "राज्य सभा या लोक सभा या" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ग) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन दावे का भी हकदार है, यहाँ-ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेंशन के साथ-साथ उप-धारा (1) के अधीन, पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस समय कोई व्यक्ति जिसने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य या क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य अथवा तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के सदस्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य के रूप में सेवा की है, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-ख की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के तत्समान पेंशन पाने का हकदार है। जहाँ किसी व्यक्ति ने ऐसे सदस्य के रूप में एक वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है, उसको पेंशन संदत्त नहीं की जाती है, किन्तु, यदि किसी व्यक्ति ने एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उसे प्रतिमास तीन सौ पचहत्तर रुपये की दर से पेंशन संदत्त की जाती है और यदि उसने तीन वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उसे प्रतिमास एक हजार रुपये की दर से पेंशन संदत्त की जाती है। अधिनियम की धारा 6-ख की उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, उस अवधि के लिए, सिवाय ऐसा पद धारण करने के लिए उसको संदेय वेतन और संदेय पेंशन के बीच अन्तर के (यदि संदेय वेतन संदेय पेंशन से कम है) जिसके दौरान वह राज्य सभा या लोक सभा अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य बन जाता है कोई पेंशन प्राप्त करने का हकदार नहीं है, धारा 6-ख की उप-धारा (3) के अधीन, जहाँ ऐसे सदस्य के रूप में पेंशन पाने का हकदार कोई व्यक्ति, किसी अन्य स्त्रोत से कोई पेंशन पाने का भी हकदार है, वहाँ सभी स्त्रोतों से (जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन भी है) उसे अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन राज्य सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होगी। संसद सदस्यों के मामले में ऐसी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए, अधिनियम की धारा 6-ख में पूर्वोक्त विषमता को हटाना और जहाँ किसी व्यक्ति ने ऐसे सदस्य के रूप में एक वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है, उसे भी प्रति मास तीन सौ पचहत्तर रुपये की दर से पेंशन संदत्त करने तथा यदि ऐसे व्यक्ति ने एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है, तो उसकी पेंशन को प्रतिमास तीन सौ पचास रुपये से बढ़ाकर सात सौ पचास रुपये करने के लिए, उपबन्ध करना भी आवश्यक हो गया है। इसके अलावा, सदस्यों को संदेय विग्रह भत्ते का एक सौ पचास रुपये से बढ़ाकर दो सौ रुपये करना भी आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

जिमला :
28 सितम्बर, 1995.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित किए जाने पर, राजकोष से प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सा 0 प्र 0 नस्ति संख्या जी 0 ए 0 डी 0 सी 0 (पी 0 ए 0) 4-21/94]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 1995 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करने हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 1995.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT
BILL, 1995**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 1995.

Amendment
of Section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "one hundred and fifty" wherever these occur, the words "two hundred" shall be substituted.

8 of 1971

Amendment
of Section
6-B.

3. In section 6-B of the principal Act—

(a) in sub-section (1-A)—

(1) Clauses (i) and (ii) shall be renumbered as clauses (ii) and (iii) and before clause (ii) renumbered, the following clause (i) shall be inserted, namely:—

“(i) if has served for a period not exceeding one year, the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem”;

(ii) in renumbered clause (ii), for the words “three hundred and seventy five”, the words, “seven hundred and fifty” shall be substituted ;

(b) in sub-section (2), in clause (ii), the words “the Council of States or the House of the People or” shall be omitted : and

(c) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present a person who has served as Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly or as a Member of the Territorial Council or as a Member of the erstwhile State of Patiala and East Punjab States Union or as a Member of Legislative Assembly or Legislative Council of erstwhile Punjab State is entitled under sub-section (1) of section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 to a pension, corresponding to his tenure as such member. Where a person has served as such member for a period less than one year is not paid any pension, but if a person has served for a period exceeding one year but less than three years, is paid pension @ Rs. 375/- per month and in case he has served for a period exceeding three years but less than five years is paid pension @ Rs. 1000/- per month. By virtue of the provisions contained under sub-section (2) of section 6-B of the Act, Ex-MLA is not entitled to any pension for the period during which such person becomes a Member of the Council of States or the House of People or of any Legislative Assembly or a Legislative Council of any Union Territory or of a State, save and except the difference between the salary payable to such person for holding such office and the pension payable (in case the salary payable is less than the pension payable). Under sub-section (3) of section 6-B, where any person is entitled to a pension as such member is also entitled to any pension from any other source then the maximum pension from all sources (including pension under the said Act) admissible to him is not to exceed the maximum pension admissible to the Grade I Officers of the State Government. There is no such maximum limit in the case of Members of Parliament. In order to give the fair deal to such persons, it has become necessary to remove the aforesaid anomaly in section 6-B of the Act and also to provide that where a person has served as such member for a period of less than one year, he may also be paid pension @ Rs. 375/- per month and also to increase the pension from Rs. 375/- to Rs. 750/- per month, if such person has served for period exceeding one year but less than three years. Apart from this it is also considered necessary to raise the halting allowance payable to Members from Rs. 150/- to 200/-.

Hence, this Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 28th September, 1995.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer, to the tune of Rs. 10.00 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

NIL

of
the

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(PA)4-21/94]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1995, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.